

चार दिवसीय सम्मेलन में संस्कृति, विरासत और वैश्विक सहयोग पर होगा मंथन



राजधानी में ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 का शुभारंभ, दस देशों के प्रतिनिधि जुटे

- ▶ **संस्कृति, विरासत और रचनात्मक उद्योगों पर होगा विचार-विमर्श।**
- ▶ **‘ज्ञान भारतम्’, ‘प्रोजेक्ट मौसम’ और ‘प्रोजेक्ट बृहत्तर भारत’ पर विशेष प्रदर्शनियां।**
- ▶ **7 अगस्त को ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव और ‘अमृतस्य मध्य प्रदेश’ की विशेष प्रस्तुति**

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: राजधानी भोपाल में बुधवार से ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन-2026 का शुभारंभ हो गया। चार दिनों तक चलने वाले इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिक्स

विदेशी प्रतिनिधियों के सामने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान होगी प्रस्तुत

सदस्य और भागीदार देशों सहित 10 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है, जहां पहले दिन अधिकारियों की बैठक और औपचारिक स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुए।

सम्मेलन का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने और सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा देना है। आयोजन स्थल पर ‘ज्ञान भारतम्’, ‘प्रोजेक्ट मौसम’ और ‘प्रोजेक्ट बृहत्तर भारत’ विषयों

पर विशेष प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं, जिनमें भारत की ऐतिहासिक धरोहर, समुद्री सांस्कृतिक संपर्क और प्राचीन सभ्यताओं की झलक आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों की विशेष व्यवस्था की गई है। दाल-बाफले, कोदो-कुटकी आधारित मिलेट व्यंजन सहित प्रदेश के अनेक पारंपरिक स्वाद मेहमानों को परोसे जा रहे हैं। वहीं कथक, लोकनृत्य, जनजातीय कला और पारंपरिक वेशभूषा पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

भी सम्मेलन का आकर्षण रहेंगी। सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, सांची स्तूप और अन्य सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। 7 अगस्त को होने वाला ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव और मध्य प्रदेश की

विशेष प्रस्तुति ‘अमृतस्य मध्य प्रदेश’ सम्मेलन के प्रमुख आकर्षण होंगे। इस प्रस्तुति में प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर, जनजातीय संस्कृति, धार्मिक परंपराएं और पर्यटन स्थलों को संगीत एवं नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

तयों अहम् है सम्मेलन?

यह सम्मेलन भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करने, ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में साझा प्रयासों को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षमता वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा।

ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने जाना भारतीय संस्कृति का वैभव

नप्र, भोपाल : ब्रिक्स सदस्य देशों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने बुधवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का भ्रमण कर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, लोक एवं जनजातीय विरासत का अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया तथा संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रतिनिधियों ने मुक्ताकाश प्रदर्शनी के अंतर्गत कुम्हार पारा, पारंपरिक तकनीकी उद्यान और हिमालयी ग्राम प्रदर्शनी का भ्रमण किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, लोक जीवन, पारंपरिक आवास, शिल्प और जनजातीय विरासत के संरक्षण के लिए संग्रहालय के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने केरल की पारंपरिक धरोहर 1001 दीपों वाले विशाल अनुष्ठानिक दीप का अवलोकन कर दीप प्रज्वलित किया। ब्रिक्स सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित विशेष प्रदर्शनियों में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा, समुद्री सांस्कृतिक संबंधों और सभ्यतागत विरासत को भी प्रदर्शित किया गया।

मप्र कांग्रेस के सभी विभाग-प्रकोष्ठ भंग, 6 जिलाध्यक्षों की छुटी तय दिल्ली में दो दिन चली समीक्षा बैठक के बाद फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस में व्यापक संगठनात्मक बदलावों का दौर शुरू हो गया है। ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने प्रदेश संगठन में बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विभागों, प्रकोष्ठों (सेल), उनके प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर के संगठनात्मक ढांचे को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। यह आदेश प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने बुधवार को जारी किया। यह निर्णय दिल्ली में पिछले दो दिनों से चल रही संगठन समीक्षा बैठक के बाद लिया गया, जिसमें प्रदेश संगठन की कार्यप्रणाली, सक्रियता और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह फैसला प्रदेश कांग्रेस के व्यापक पुनर्गठन की पहली कड़ी माना जा रहा है।

प्रदेश कार्यकारिणी पर भी गिर सकती है गाज

संगठनात्मक फेरबदल केवल विभागों और प्रकोष्ठों तक सीमित नहीं रहेगा। पार्टी के भीतर चर्चा है कि एमपीसीसी की मौजूदा प्रदेश कार्यकारिणी को भी जल्द भंग किया जा सकता है। इसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन कर संगठन को पूरी तरह नए स्वरूप में खड़ा किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस ने पिछले वर्ष अगस्त में नियुक्त किए गए जिलाध्यक्षों के कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन कराया है। पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षों के प्रदर्शन को चार श्रेणियों ए, बी, सी और डी में वर्गीकृत किया है।

जल्द बनेगा नया संगठनात्मक ढांचा

प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व अब प्रदेश में पूरी संगठनात्मक संरचना को नए सिरे से तैयार करने की तैयारी में है। पार्टी का लक्ष्य आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए संगठन को अधिक सक्रिय, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाना है। सूत्रों का कहना है कि नए गठन में जमीनी स्तर पर सक्रिय और संगठन के लिए लगातार काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

मंत्री सारंग और पटेल कार्यकर्ताओं से मिले

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मंत्री विश्वास सारंग एवं लखन पटेल ने बुधवार को भाजपा पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याएं और सुझाव सुने। दोनों मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न मामलों पर संबंधित अधिकारियों से तत्काल चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। जिन मामलों का मौके पर समाधान संभव था, उनका तत्काल निराकरण कराया गया, जबकि अन्य प्रकरणों को आवश्यक कार्रवाई और शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया।



कचव योजना से किसानों को मिलेगा नया संबल सरसों-धान भी भावांतर योजना में शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के खेतों से लेकर उनके खातों तक हर स्तर पर उनकी जरूरतों का ध्यान रख रही है।

उन्होंने नर्मदापुरम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को भोपाल से वरुंअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसान हितैषी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई कचव योजना से उन किसानों को राहत मिलेगी, जो सहकारी खातों में पुरानी गड़बड़ियों या जांच लंबित होने के कारण नए कृषि ऋण और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित थे। योजना के माध्यम से ऐसे किसानों



को मुख्यधारा में लाकर ऋण और अन्य सुविधाओं का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिकॉर्ड 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस का लाभ दिया है। अब सरसों और

धान को भी भावांतर योजना में शामिल किया गया है। साथ ही कोदो-कुटकी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी और बोनस की व्यवस्था लागू की गई है। पात्र किसानों के लिए मृंगा उत्पाजनी की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है।

बस परिवहन व्यवस्था में बदलाव से पहले पुनर्विचार की मांग

नप्र, भोपाल : प्रदेश में बस परिवहन व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव को लेकर पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि वर्तमान परिवहन व्यवस्था पहले की

- ▶ **पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा- मौजूदा व्यवस्था में सुधार किया जाए, छोटे संचालकों के हित सुरक्षित रहें**
- ▶ **प्रमुख मार्ग निजी कंपनियों को सौंपने पर जताई चिंता, हड़ताल पर अड़े बस संचालक**

तुलना में बेहतर कार्य कर रही है। यदि इसमें कोई कमी है तो उसे दूर किया जाए, लेकिन ऐसी नई व्यवस्था लागू करने से बचना चाहिए, जिससे छोटे बस संचालकों और उनसे जुड़े हजारों परिवारों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो। श्री कोठारी ने पत्र में उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के समय यात्रियों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं और निगम लगातार घाटे में था। बाद में निजी बस संचालकों को अवसर मिलने से परिवहन व्यवस्था में सुधार हुआ तथा यात्रियों को अधिक विकल्प उपलब्ध हुए।

उन्होंने यह भी आशंका जताई कि प्रदेश के प्रमुख और लाभकारी मार्ग सीमित निजी कंपनियों को सौंपने की योजना पर विचार किया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत छोटे और मध्यम बस संचालकों के हित प्रभावित होंगे। अनेक संचालकों ने ऋण लेकर बसें खरीदी हैं और नई व्यवस्था उनके लिए आर्थिक कठिनाइयां खड़ी कर सकती है। उन्होंने सरकार से किसी भी निर्णय से पहले उसके दूरगामी प्रभावों पर गंभीरता से विचार करने तथा मौजूदा व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने का आग्रह किया।

जहां गुरु विशिष्ट, वहां शिष्य भी विशिष्ट : दंदरौआ सरकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: श्री पीताम्बरा पीठ संस्कृत महाविद्यालय, दतिया एवं कालिदास संस्कृत अकादमी, उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का समापन बुधवार को पीठ परिसर में हुआ। समापन समारोह में संतों एवं विद्वानों ने गुरु-शिष्य परंपरा, तंत्रागम और संस्कृत भाषा के महत्व पर विचार व्यक्त किए।

समारोह के मुख्य अतिथि महंत रामदास महाराज (दंदरौआ सरकार) ने कहा कि जहां गुरु विशिष्ट होते हैं, वहां के शिष्य भी विशिष्ट बनते हैं। उन्होंने कहा कि श्री पीताम्बरा पीठ संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थियों की प्रतिभा इसका उदाहरण है। उन्होंने हिंदी को अर्थ की, अंग्रेजी को रोजगार की और संस्कृत को मोक्षदायिनी भाषा बताते हुए संस्कृत अध्ययन को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

मुख्य वक्ता महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के कुलगुरु प्रो. शिवशंकर मिश्र ने तंत्रागम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज को तंत्र के वास्तविक स्वरूप से परिचित होना चाहिए। उन्होंने भवानी अष्टकम को पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में मां भवानी ही अपने भक्तों की रक्षा करती हैं।



कालिदास संस्कृत अकादमी, उज्जैन के निदेशक डॉ. गोविंद गंधे ने संगोष्ठी की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए आयोजन से जुड़े सभी विद्वानों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। वहीं आचार्य पं. चंद्रमोहन दीक्षित ने वामाचार और दक्षिणाचार के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि तंत्र के संबंध में समाज में कई भ्रांतियां व्याप्त हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। संस्कृत शोध पीठ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी के निदेशक प्रो. वी.वी. त्रिपाठी ने तंत्रागम के वाममार्ग और दक्षिणमार्ग पर प्रकाश डालते हुए तंत्र के शुद्ध स्वरूप को समझने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री

पीताम्बरा पीठ के न्यासी एवं महाविद्यालय शासी निकाय के अध्यक्ष प्रो. धीरेन्द्र सिंह चंदेल ने कहा कि यह संगोष्ठी तंत्रागम अध्ययन और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने आयोजन की सफलता के लिए श्री पीताम्बरा पीठ की अध्यक्ष श्रीमंत वसुंधरा राजे सिंधिया तथा पीठ के सभी न्यासियों का आभार व्यक्त किया।

समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वैदिक मंगलाचरण से हुआ। स्वागत भाषण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. हरेंद्र कुमार भार्गव ने दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सुजाता शांडिल्य ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन पीठ के व्यवस्थापक डॉ. सी.एम. मिश्र ने प्रस्तुत किया।

जनहित सर्वोपरि रखकर करें कार्य : तोमर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अधिकारियों से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नवाचार और पारदर्शिता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। वे बुधवार को विधानसभा परिसर में सहकारिता, श्रम विभाग तथा उप पुलिस अधीक्षक सहित लगभग 60 प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। ये अधिकारी आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन भ्रमण पर पहुंचे थे। श्री तोमर ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति योजनाओं और कानूनों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों में दिखाई देती है।



अभियान

हर शुक्रवार चलेगा मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान...

अधिकारियों को फील्ड में रहना होगा अनिवार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रदेश में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागयुक्तों और जिला कलेक्टरों को इसके सफल संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अभियान का उद्देश्य क्षेत्रीय भ्रमण, निरीक्षण और जनसंवाद के

माध्यम से आम नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी तथा लोक सेवाओं का समय-सीमा में लाभ सुनिश्चित करना है। निर्देशों के अनुसार अभियान के दौरान प्रत्येक शुक्रवार को अधिकारियों के लिए फील्ड भ्रमण अनिवार्य रहेगा। इस दिन विभागीय स्तर पर नियमित ऑनलाइन या ऑफलाइन समीक्षा बैठकों का आयोजन नहीं किया जाएगा, ताकि अधिकारी सीधे जनता के बीच पहुंच सकें।

अभियान के चार प्रमुख आधार संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी तय किए गए हैं। सभी विभागों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित शिकायतों और आवेदनों की साप्ताहिक समीक्षा कर उनका समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों से भ्रमण के दौरान सादगी और मितव्ययिता अपनाने

अनुच्छेद 370 हटने के सात वर्ष पूरे मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति के सात वर्ष पूरे होने पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय भारत की एकता, अखंडता और संवैधानिक समानता को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख विकास, लोकतंत्र और समान अधिकारों की मुख्यधारा से जुड़े हैं तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकीकरण को सशक्त करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय बताया।

पर भी जोर दिया है। वाहन पूलिंग अनावश्यक वाहनों के उपयोग से को प्राथमिकता देने और बचने के निर्देश दिए गए हैं।